ई–गवर्नेन्सः अगस्त से शुरू हो जाएगा जन सेवा स्टेट पोर्टल

- *उत्तर प्रदेश ई–गवर्नेन्स को प्राथमिकता पर लागू करने वाला पहला बड़ा राज्य*
- *मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया*

लखनऊ, 19 जुलाई 2012

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सूचना प्रोद्यौगिकी के प्रयोग से जन सामान्य को स्थानीय स्तर पर पारदर्शी रूप से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के मन्तव्य को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 01 अगस्त 2012 से राज्य के सभी जिलों में इसके लिए 'स्टेट–पोर्टल' की शुरूआत करने का निर्णय लिया। मुख्य सचिव, जावेद उस्मानी ने इस सन्दर्भ में आज यहाँ एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनिल कुमार गुप्ता और प्रमुख सचिव सूचना प्रोद्यौगिकी, जीवेश नन्दन सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश में ई–गवर्नेन्स को ठीक से लागू करने के लिए आयोजित विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा, "सूचना प्रोद्यौगिकी के उपयोग से सरकार तथा जनता के बीच जनसेवा से सम्बन्धित सम्पर्क को कार्यालय से इन्टरनेट आधारित पोर्टल पर स्थानान्तरित करने से पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना होगी तथा प्रशासनिक अधिकारों के दुरूपयोग को रोका जा सकेगा। अतः यह कदम अत्यन्त महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण वे स्वयं करेंगे तथा सभी संबंधित विभागों को इसके लिए जरूरी अवस्थापना व यंत्रों सहित प्रशिक्षण को समय से पूरा कर लेना चाहिए। 01 अगस्त 2012 से स्टेट पोर्टल के शुरू हो जाने के बाद इस संबंध में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस पहल को जन सामान्य व प्रदेश के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बताते हुए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनिल कुमार गुप्ता ने कहा, "कुछ छोटे राज्यों को छोड़ कर उत्तर प्रदेश एकमात्र बड़ा राज्य है जहाँ सूचना प्रोद्यौगिकी के प्रयोग से इतने बड़े स्तर पर नागरिक विशेष सेवाओं को उपलब्ध कराने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है।" औद्योगिक विकास आयुक्त ने कहा कि न केवल इस योजना को सुचारू रूप से लागू करना जरूरी है बल्कि एक बार शुरू हो जाने पर जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाने के कारण सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ऐसा मानना है कि छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित करने से सूचना प्रोद्यौगिकी के बारे में जागरुकता बढ़ेगी तथा रोजगार के नये अवसर मिलेंगे, इसलिए भी ई–गवर्नेन्स योजना के निरन्तर सुधार व उन्नयन करते रहना होगा।

इसके पहले प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रमुख सचिव सूचना प्रोद्यौगिकी जीवेश नन्दन ने बताया कि नागरिक इस स्टेट पोर्टल पर अपने आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जन सेवा/लोकवाणी केन्द्र में जाकर दाखिल कर सकेंगे, फिर संबंधित विभाग उस पर यथोचित कार्यवाही कर प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज पुनः पोर्टल पर निश्चित समयावधि में अपलोड कर देंगे, जिसको नागरिक जन सुविधा केन्द्र या लोकवाणी केन्द्र पर जाकर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भारत सरकार के ई–गवर्नेन्स कार्यक्रम को लागू करने वाला एक अग्रणी राज्य है।

आगामी माह में शुरू होने वाले स्टेट पोर्टल के माध्यम से आठ विभागों की 26 सेवाओं को जनता तक जन सेवा केन्द्रों व लोकवाणी केन्द्रों से पहुँचाया जाएगा। इसके लिए एकल बिन्दु के रूप में स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे का उपयोग किया जाएगा। प्रथम चरण में आठ विभाग, यथा– पंचायती राज, राजस्व, श्रम, नगर विकास, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास तथा खाद्य एवं रसद आपूर्ति अपनी सेवाएं इसके माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इसमें कई आवेदन पत्र व प्रमाण पत्र, जैसे– निवास, जाति, आय, खतौनी, राशन कार्ड, रोज़गार पंजीयन, जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र, विकलांग व्यक्तियों को ऋण, वृद्धावस्था पेंशन, कुटुम्ब रजिस्टर की कॉपी, विधवा पेंशन, दहेज उत्पीड़ित महिलाओं को वित्तीय व विधि सहायता, आदि सम्मिलित हैं।